an>

Title: Need to reorient economic policy giving adequate emphasis on labour-oriented manufacturing sector ensuring livelihood to all in the country.

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : आज भारत प्राकृतिक आपदाओं के संकट से घिरा है। असामयिक एवं अनिश्चित तथा अति वÂ◌ा◌ा़न, भूस्खलन और पर्वतों का ढहना आम होता जा रहा है। प्रकृति के कहर के आगे मानव बेबश है। परंतु वास्तविकता यह है कि मानव के कारण ही प्रकृति का कहर है। विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति का दोहन और दुरूपयोग करने में विगत वÂ◌ा◌ा◌ें में कोई हिचक नहीं दिखाई। एक वÂ◌ा़न में सरकारों ने 35.86 प्रतिशत हेक्टेयर जंगल की भूमि को कथित विकास के नाम पर उजाड़ा है। देश का वायुमंडल, जलप्रवाह एवं वÂ◌ा◌ा़न की अनिश्चितता जो मानव को जीवन देती है, आज वहीं मानव के विनाश का कारण बन गया। जब मानव ही नहीं रहेगा तो विकास कैसा और किसके लिए ? गत दो दशकों में विकास के नाम पर देश में जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे दरिद्रता तथा दीनता नहीं घट पाई। वÂ◌ा़न 2013 में सरकार द्वारा 67 प्रतिशत आबादी को 1 रूपये और 2 रूपये किलो अनाज देश की आम गरीब जनता को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देने की नीति बनाई गई। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश में दरिद्रता और दीनता कम नहीं हुई।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त नीतियों में परिवर्तन कर देश की विकास दर के लिए स्वदेशी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। देश में विकास के कार्यक्रम, देश की क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य और साधनों के आधार पर तय किया जाए। सेवा क्षेत्र और मूल्यवर्धक आर्थिक गतिविधियों के स्थान पर उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। श्रम प्रधान तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देकर देश के प्रत्येक परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए तथा दीनता व दरिद्रता को देश से देर किया जाए।